नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. UPHIN/25/A1698

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 076
दि. 15.07.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

'अयोध्या की आड़ में देश की अस्मिता और आस्था पर प्रहार', सीएम योगी बोले- हिंदू धामों को बनाया जा रहा निशाना

यूपी 'बीमारू' राज्य से निकलकर शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल। कानून व्यवस्था सुधरी, निवेश बढ़ा, 50 लाख करोड़ के प्रस्ताव।

9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां, ओडीओपी से रोजगार।

(जीएनएस)।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है, वे देश की अस्मिता व आस्था पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के मामले में ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी निष्पक्ष जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

नैतिक आधार पर इस्तीफे भी हुए हैं। लेकिन, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की आड़ में जो लोग आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू धामों पर प्रहार कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो गरीबों के हक पर डकैती डालते थे और हनुमानगढ़ी जैसे पवित्र स्थल पर नमाज पढ़वाने का कुत्सित प्रयास करते थे। सीएम ने जनता से राष्ट्रीय मूल्यों को ठेस पहुंचाने वाली ऐसी ताकतों से सजग रहने की अपील की।

मुख्यमंत्री मंगलवार को लखनऊ में 'रिपब्लिक भारत' न्यूज चैनल के विशेष कॉन्क्लेव 'ऊंचाइयों पर यूपी' को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने पिछले 9 वर्षों से अधिक समय के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में आए युगांतकारी परिवर्तनों और उपलब्धियों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और डबल इंजन सरकार के दृढ़ संकल्प से आज उत्तर प्रदेश 'बीमारू' राज्य की श्रेणी से बाहर निकलकर देश की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है।

बेटियों को यूपी से बाहर भेज देते थे लोग

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में 2017 से पहले हर तीसरे दिन दंगा होता था, महीनों तक कर्फ्यू रहता था। बेटी व व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। 35 से ज्यादा ऐसे जनपद थे, जहां लोगों ने बेटी को यूपी के बाहर हॉस्टल या रिश्तेदार के घर भेजकर पढ़ाई कराई। अन्य लोग बेटियों की सुरक्षा के लिए उन्हें स्कूल भेजना ही बंद कर देते थे। व्यापारी को पता नहीं होता था कि घर लौट पाएगा या नहीं। किसान अपने खेत में जाने से डरता था।

विस्फोटों से जुड़ता था यूपी का नाम

सीएम ने कहा कि उस वक्त देश में कहीं विस्फोट होता था, तो यूपी का नाम जुड़ता था। पिछली सरकारों में दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित किया जाता था। माफियाओं के सामने सरकारें नतमस्तक होकर नाक रगड़ती थीं। नई पीढ़ी को यह जानकारी देने की आवश्यकता है। लेकिन, पिछले 9 वर्षों में हमारी पहचान दंगा, कर्फ्यू और उपद्रवमुक्त उत्तर प्रदेश के रूप में बनी है। उत्तर प्रदेश में अब बेटी, व्यापारी समेत हर व्यक्ति सुरक्षित है।

यूपी को मिले 50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा का वातावरण नहीं बना होता तो कोई निवेशक यूपी में नहीं आता। हमने 2017 अक्टूबर में इन्वेस्टर समिट की योजना बनाई और इसके लिए पॉलिसी तैयार की। नतीजा यह कि यूपी को 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिसमें 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट धरातल पर उतारे जा चुके हैं। 2017 के पहले

लखनऊ की चिकनकारी, फिरोजाबाद का ग्लास, मुरादाबाद का पीतल, मेरठ का स्पोर्ट्स, भदोही का कालीन व बनारस का साड़ी उद्योग दम तोड़ रहा था।

उद्यमियों व कारोबारियों के पास घर बैठने के सिवा कोई चारा नहीं था। डबल इंजन सरकार बनी तो हमने 'एक जिला-एक उत्पाद' (ओडीओपी) के रूप में इनकी ब्रांडिंग की। 75 जिलों के 79 उत्पादों को जीआई टैग के साथ जोड़ा गया है। ओडीओपी के तहत वर्तमान में 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी में कार्यरत हैं, जिनमें सवा तीन करोड़ युवाओं को रोजगार मिला है। यूपी आज 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ओडीओपी उत्पाद निर्यात कर रहा है।

राज्य बीमारू नहीं, बीमार थी मानसिकता

सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों में पिछड़ापन, अव्यवस्था, दंगे, गुंडागर्दी, कर्फ्यू, बेरोजगारी ही यूपी की पहचान बन चुकी थी। खामियाजा बेरोजगारी के रूप में युवाओं को भुगतना पड़ता था। सरकार बनाने के बाद हमने पहली कैबिनेट बैठक में अन्नदाता किसानों को राहत देने का निर्णय किया, लेकिन खजाना खाली था। बैंकर फोन नहीं उठा रहे थे।

तत्कालीन वित्त सचिव तबीयत खराब होने की बात कहकर कार्यभार से मुक्त करने के लिए कह रहे थे। लेकिन, हमने ठोस फैसले करने शुरू किए तो परिणाम सामने आने शुरू हो गए। वास्तव में यूपी बीमारू नहीं था, बीमार वो मानसिकता थी जो 2017 से पहले शासन कर रही थी। इसी मानसिकता ने किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया था। युवाओं के सामने पहचान का संकट और हर व्यक्ति में असुरक्षा का भाव पैदा किया था।

आज यूपी का बजट 9 लाख करोड़ से अधिक

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी के बजट को 3 लाख करोड़ से बढ़कर 9 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। 2016-17 में यूपी की कुल जीएसडीपी 12 लाख करोड़ रुपये थी, जो अब 36 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। तब प्रति व्यक्ति आय महज 43 हजार रुपये थी, जो अब 1.20 लाख रुपये से अधिक है।

उत्तर प्रदेश में महिला कार्यबल केवल 12 प्रतिशत था, आज वह 38 प्रतिशत से अधिक है। बेरोजगारी दर 19 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत से भी कम रह गई है। यह तस्वीर नए उत्तर प्रदेश को पेश करती है।

यूपी ने रची विकास की महागाथा

सीएम ने कहा कि अब देश के कुल एक्सप्रेसवे में 60 प्रतिशत उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे व देश का सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे भी प्रारंभ हो चुका है। सोमवार से लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे शुरू हुआ है। अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी हो या जिला मुख्यालय, सभी फोरलेन से जुड़े हैं।

देश का पहला इनलैंड वॉटरवे, रैपिड रेल व रोपवे के साथ जल्द ही जुड़ने वाला वाराणसी शहर भी यूपी में है। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट व मेट्रो का संचलान यूपी में हो रहा है। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क भी यूपी के पास है। ये सब 9 वर्ष पहले सिर्फ सपना था।

गन्ना, चीनी व एथेनॉल उत्पादन में नंबर-1 यूपी

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले यूपी सरकार ने आम महोत्सव आयोजित किया, जिसमें हजारों टन आम निर्यात किया गया। दुनियाभर के लोग यूपी का आम खरीदने के लिए लाइन में खड़े थे। 2014 से पहले किसान सुविधाओं के अभाव में आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। 2007 से 2017 के बीच यूपी की 29 चीनी मिलें बंद हुईं या बेच दी गईं।

3-3 करोड़ में बेची जाने वाली चीनी मिलों की जमीन ही सैकड़ों करोड़ रुपये की थी। हमारी सरकार ने 2017 से अब तक 3.23 लाख करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों के खातों में किया है। 122 चीनी मिलों का संचालन किया जा रहा है। देश के अंदर गन्ना, चीनी व एथेनॉल उत्पादन में यूपी नंबर-1 है।

24 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा

सीएम ने कहा कि यूपी में पिछले 9 वर्ष में 24 लाख हेक्टेयर लैंड को सिंचाई सुविधा दी गई है। बाणसागर परियोजना दशकों से लंबित थी, जिसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पूरा किया। 2.5 लाख हेक्टेयर लैंड को इससे सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। बुंदेलखंड में अर्जुन सहायक परियोजना दशकों से लंबित थी, जिसे पूरा करवाया गया।

सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को योजना आयोग ने 1970 के दशक में स्वीकृत किया था। 1977 में इसकी आधारशिला रखी गई, लेकिन यह कभी पूरी नहीं हो पाई। तब इस पर कुल 100 करोड़ खर्च होने थे, लेकिन समय पर कार्य न होने के कारण 10 हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़े।

पीएम मोदी देंगे कानपुर को बड़ी सौगात, 17 जुलाई को पनकीधाम अमृत भारत स्टेशन का यहां से करेंगे लोकार्पण

पनकीधाम स्टेशन पर आधुनिक प्रतीक्षालय, दिव्यांगजन सुविधाएं और बेहतर यात्री सुविधाएं विकसित की गई हैं

अमृत भारत स्टेशन योजना से लाखों श्रद्धालुओं और यात्रियों को बेहतर एवं सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा

जागरण संवाददाता, कानपुर। प्रयागराज मंडल के तीन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 जुलाई को वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करेंगे। हरियाणा के जींद से वे पनकीधाम, फतेहपुर और विंध्याचल स्टेशन को जनता को सौंपेंगे।

कानपुर के पनकी धाम स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से विकसित किया गया है। स्टेशन पर बेहतर यात्री सुविधाएं, आकर्षक भवन, आधुनिक प्रतीक्षालय, दिव्यांगजन अनुकूल व्यवस्थाएं, बेहतर प्रकाश व्यवस्था

और सुगम आवागमन की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। स्टेशन का नया स्वरूप क्षेत्र की धार्मिक और यातायात आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का होगा ठहराव

प्रयागराज रेल मंडल के पीआरओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि पनकी धाम स्टेशन के विकसित होने से भविष्य में लाखों श्रद्धालुओं और यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। पनकीधाम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की आवाजाही आसान होगी। वहीं भविष्य में कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। इससे कानपुर के पश्चिमी क्षेत्र के यात्रियों को कानपुर सेंट्रल पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी।

कार्यक्रम प्रसारण की तैयारी की जा रही

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित फतेहपुर और विंध्याचल स्टेशन भी यात्रियों को आधुनिक और सुविधाजनक रेल यात्रा का अनुभव देंगे। पीआरओ ने बताया कि 17 जुलाई को होने वाले लोकार्पण कार्यक्रम के लिए रेलवे प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। स्टेशनों पर कार्यक्रम के प्रसारण और स्थानीय आयोजन की भी व्यवस्था की जा रही है।

ई20 पेट्रोल पर बवाल के बीच अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा लेटर, कर दी ये खास अपील

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर घमासान थमता नहीं दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इस बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। ई20 पेट्रोल को लेकर लोगों की चिंताओं पर चर्चा के लिए उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात का समय मांगा है। इसके साथ ही उन्होंने ये अनुरोध किया कि पेट्रोल पंपों पर शुद्ध पेट्रोल और ई20 पेट्रोल दोनों विकल्प उपलब्ध कराए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की कीमतें कम की जाएं।

केजरीवाल का पीएम मोदी को लेटर

प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में अरविंद केजरीवाल ने उनसे मुलाकात का समय मांगा है।

उन्होंने पत्र में कहा कि बैठक के दौरान वह ई20 पेट्रोल से जुड़े तकनीकी मुद्दों और इस विषय पर लोगों से मिली प्रतिक्रियाओं को प्रधानमंत्री के सामने रखना चाहते हैं। AAP नेता ने कहा कि पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को यह विकल्प मिलना चाहिए कि वे शुद्ध पेट्रोल या ई20 पेट्रोल में से अपनी पसंद का ईंधन खरीद सकें।

'अगर कोई व्यक्ति शुद्ध पेट्रोल लेना चाहता तो..'

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति शुद्ध पेट्रोल लेना चाहता है तो उसे यह विकल्प मिलना चाहिए और जो लोग ई-20 पेट्रोल लेना चाहते हैं, उन्हें भी वह सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। 'आप' प्रमुख ने कहा कि लोगों से बातचीत करने और ई20 पेट्रोल को लेकर उनकी चिंताओं को समझने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। केजरीवाल ने ई20 पेट्रोल की कीमतें कम करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से सामान्य पेट्रोल की तुलना में माइलेज कम मिलता है, इसलिए इसकी कीमत कम होनी चाहिए।

आम जनता के दर्द पर कब बोलेंगे पीएम मोदी : जयराम

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता के दर्द पर कब बोलेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में दावा किया कि मोदी सरकार के 12 वर्षों का यही है असली सारः झूठे वादों की बहार और जनता पर महंगाई और बेरोजगारी का क्रूर वार। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में महंगाई ने आम परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है।

जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में कहा, 'अब खुद सरकारी आंकड़े भी बता रहे हैं कि जून में खुदरा महंगाई 17 महीने के उच्चतम स्तर 4.38 फीसदी पर पहुंच गई है, जबकि ग्रामीण भारत में यह 4.74 फीसदी है। जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि महंगाई के साथ अब बैंकों की ब्याज दरें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिससे मध्यम वर्ग पर घर और गाड़ी की मासिक किस्त का बोझ भी बढ़ सकता है।

कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि मुनाफा पूंजीपतियों की जेब में और बोझ आम जनता की पीठ पर क्यों? कांग्रेस महासचिव ने यह भी प्रश्न किया कि पूंजीपतियों के संरक्षक प्रधानमंत्री मोदी आम जनता के दर्द पर कब बोलेंगे? पूंजीपतियों के

बेंगलुरु में देर रात तक FIFA World Cup मैच देख सकेंगे फैंस, DK शिवकुमार ने होटल-रेस्टोरेंट्स को दी बड़ी राहत

देश में इन दिनों फीफा वर्ल्ड कप का खुमार चढ़ा हुआ है। फुटबॉल प्रेमी देर रात तक मैच देखते हैं। ऐसे में कर्नाटक सरकार ने फुटबाल प्रेमियों को बड़ी राहत दी है। उट डी.के. शिवकुमार ने कहा है कि बेंगलुरु में फीफा विश्व कप के अहम मुकाबलों के दौरान होटल और रेस्तरां देर रात तक खुले रह सकेंगे। ताकि खेल प्रेमी बिना किसी परेशानी के मैचों का आनंद ले सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि फुटबॉल केवल एक खेल नहीं, बल्कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों को जोड़ने वाला एक ऐसा जुनून है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं।

'सिस्टम की नाकामी के लिए उम्मीदवारों को सजा क्यों?' राहुल गांधी ने सीएम फडणवीस से की तीन मांगे

(जीएनएस)।

महाराष्ट्र में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पेपर लीक मामले को लेकर विपक्षी पार्टी हमलावर हो गए है। पेपर लीक होने के कारण लगभग छह लाख उम्मीदवारों का भविष्य अधर में अटका हुआ है लेकिन अभी तक परीक्षा की दोबारा तारीख घोषित नहीं की गई है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दें पर महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को घेरा है।

राहुल गांधी ने एक्स पर एक लंबी-चौड़ी पोस्ट हिंदी में शेयर की है और सरकार से सीधा सवाल करते हुए पूछा है कि , "गलती सिस्टम की है, तो फिर मेहनत से पढ़ाई करने वाले उम्मीदवारों को इसकी सजा क्यों दी जा रही है?" इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से तीन अहम मांग की है।

छह लाख उम्मीदवार का भविष्य अधर में

राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा, "महाराष्ट्र TET का पेपर लीक

हो गया और परीक्षा रद्द कर दी गई। छह लाख उम्मीदवार का भविष्य अधर में है। दो हफ़्ते बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई नई तारीख घोषित नहीं की गई है। दोषी खुलेआम घूम रहे हैं, सिस्टम को बेदाग माना जा रहा है, और नतीजा उसे भुगतना पड़ रहा है जिसने ईमानदारी से कड़ी मेहनत की थी। देश के भविष्य के शिक्षकों के साथ खिड़वाड़ है ये, उन्होंने आगे लिखा, ये देश के मौजूदा और भविष्य के शिक्षक हैं, जिनके हाथों में भारत का भविष्य है। ये वे लोग हैं जिन्होंने तैयारी करने, फॉर्म भरने, फीस देने और दूर-दराज के परीक्षा केंद्रों तक यात्रा करने में कई साल बिताए; अब, वे बस इंतजार कर रहे हैं-बिना किसी तारीख और बिना किसी जवाब के।

राहुल गांधी ने देवेंद्र फडणवीस के सामने रखीं तीन मांगें, टीईटी की परीक्षा की नई तारीख अभी घोषित कीजिए। पेपर लीक के लिए जिम्मेदार पर कार्रवाई हो, अभ्यर्थी पर नहीं। इस पेपर लीक के कारण जिन अभ्यर्थियों का साल बर्बाद हुआ है, उन्हें उम्र सीम में छूट दी जाए।

'केजरीवाल, ताहिर हुसैन के आप लिंक और दिल्ली दंगों का जवाब दें', सीएम रेखा गुप्ता का सवाल, साजिश

(जीएनएस)।

साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के जख्म एक बार फिर हरे हो गए हैं। आईबी (IB) अधिकारी अंकित शर्मा हत्या के मामले में 13 जुलाई को कड़कड़डूमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस फैसले के आते ही दिल्ली की सियासत का पारा चढ़ गया है। इस मामले पर अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है।

उन्होंने साफ कहा है कि इस पूरी साजिश के पीछे छिपे चेहरों को दिल्ली की जनता के सामने बेनकाब होना ही पड़ेगा। अदालत से ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने के बाद दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सीधे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पर हमला बोला।

ताहिर हुसैन के दोषी पाए जाने पर क्या बोलीं CM रेखा गुप्ता?

रेखा गुप्ता ने कहा,

"ताहिर हुसैन दिल्ली और उसके लोगों के खिलाफ जुर्म का दोषी है, उसके कामों से हजारों लोगों को तकलीफ हुई और सैकड़ों जानें गईं। आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन से लिंक और उसे मिली पॉलिटिकल मदद को देखते हुए, क्या अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जवाब देंगे कि उन्होंने दिल्ली में दंगे भड़काने के ऐसे और कितने काम करवाए हैं? उन दंगों के दौरान जो हुआ, उससे दिल्ली के लोगों को बहुत नुकसान हुआ। उस वक्त हुए नरसंहार, पथराव, तेजाब हमलों और नाले में फेंकी गई लाशों के दर्द को दिल्ली कभी नहीं भूलेगी।"

रेखा गुप्ता ने कहा, "दिल्ली दंगों में पत्थरबाजी से लेकर हिंसा की घटनाओं ने राजधानी को झकझोर दिया। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मारे गए, यहां तक कि उन पर एसिड फेंका गया और फिर उन्हें नालियों में फेंक दिया गया। ताहिर हुसैन को कोर्ट का सजा देना सच में उन लोगों को इंसाफ देना दिखाता है जिन्होंने उन कामों में अपनी जान गंवाई।

पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

पहलगाम आतंकी हमले की जांच में ठक्अ की एक बड़ी कानूनी जीत हुई है। जम्मू की एक अदालत ने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद 26/11 हमले के मास्टरमाइंड के खिलाफ 'ट्रायल इन एब्सेंशिया' यानी आरोपी की गैरमौजूदगी में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हाफिज सईद को पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बताया है। एनआईए की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हमले की पूरी साजिश पाकिस्तान में बैठकर रची गई और इसमें हाफिज सईद की मुख्य भूमिका रही।

नवसर्जन संस्कृति हिन्दी

JioTV CHENNAL NO. 2063

Jio Air Fiber · Jio Tv + · Jio Fiber · Daily Hunt · ebaba Tv · Dish Plus

DTH live OTT · Rock TV · Airtel · Amezone Fire · Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

'जहां ठाकुर-पंडितों की बस्ती, वहां सड़क सुविधा; दलित-पिछड़ों की बस्ती बदहाल', सपा सांसद एसपी सिंह पटेल का बयान

(जीएनएस)।

प्रतापगढ़ः समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रतापगढ़ सांसद डॉ. एसपी सिंह पटेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सांसद यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि "जहां ठाकुर और पंडितों की बस्ती है, वहां सड़क बनी हुई है, लेकिन जहां दलित और पिछड़े समाज की बस्ती है, वहां आज तक सड़क नहीं बनी है।" उनके इस बयान को लेकर जिले की राजनीति गरमा गई है। सोशल मीडिया पर भी पक्ष और विपक्ष में लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

सांसद ने लोकसभा क्षेत्र के दौरे का किया जिक्र

वायरल वीडियो में एसपी सिंह पटेल दावा करते हैं कि उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र की पांचों विधानसभा सीटों का दौरा किया। इस दौरान उन्हें अधिकांश स्थानों पर यही स्थिति देखने को मिली कि दलित और पिछड़े समाज की बस्तियों में सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।

उन्होंने कहा कि अब उनकी प्राथमिकता ऐसी बस्तियों में सड़क निर्माण कराना होगी, ताकि विकास का

लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंच सके।

बीजेपी ने साधा निशाना

सांसद के वायरल वीडियो पर भाजपा की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। भाजपा के मीडिया प्रभारी राघवेंद्र शुक्ला ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास कार्य जाति विशेष को ध्यान में रखकर किए जाते थे।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' की नीति पर काम कर रही है और बिना किसी भेदभाव के प्रदेश में विकास कार्य कराए जा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर बंटी राय

सांसद के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। एक वर्ग का कहना है कि सांसद वंचित और पिछड़े इलाकों के विकास की बात कर रहे हैं, इसलिए उनके बयान को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि एक सांसद पूरे लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए सार्वजनिक मंच से इस तरह का बयान देना उचित नहीं है। फिलहाल यह वीडियो प्रतापगढ़ की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

कौन हैं एसपी सिंह पटेल?

डॉ. एसपी सिंह पटेल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। वे लगातार दो बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद (एमएलसी) के सदस्य रह चुके हैं। उनका पहला कार्यकाल 5 मई 2002 से 4 मई 2008 और दूसरा कार्यकाल 5 मई 2008 से 4 मई 2014 तक रहा।

इसके बाद वर्ष 2014 से 2020 तक उनकी पत्नी कांति सिंह उसी सीट से विधान परिषद सदस्य रहीं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में एसपी सिंह पटेल समाजवादी पार्टी के टिकट पर प्रतापगढ़ से सांसद निर्वाचित हुए।

शाह-योगी की दिल्ली में मुलाकात के मायने, क्या अयोध्या कांड के बाद तैयार हुआ 'मिशन 2027' का प्लान!

उत्तर प्रदेश में साल 2027 के महामुकाबले से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में मुलाकात ने सियासी पारा बढ़ा दिया है. माना जा रहा है कि अयोध्या में 'चंदा चोरी कांड' के बाद हालिया यूपी कैबिनेट विस्तार और अखिलेश यादव के 'पीडीए पॉलिटिक्स' को लेकर चर्चा हुई होगी. साथ ही यूपी चुनाव 2027 को लेकर एक आक्रामक मेगा प्लान तैयार किया गया होगा.

(जीएनएस)।

नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सबसे बड़ी घेराबंदी शुरू कर दी है. पिछले लोकसभा चुनाव में अयोध्या समेत यूपी के कुछ हिस्सों में लगे राजनीतिक झटके के बाद, भाजपा आलाकमान फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है. इसी सिलसिले में देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मंगलवार को कर्तव्य भवन दिल्ली में हुई एक बेहद महत्वपूर्ण और लंबी बैठक ने देश के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है. यह मुलाकात महज एक शिष्टाचार भेंट नहीं थी, बल्कि यह दिल्ली और लखनऊ के बीच उस 'पावर ट्यूनिंग'

का हिस्सा है, जो 2027 में विपक्ष के तमाम समीकरणों को ध्वस्त करने के लिए बुनी गई है.

लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में भाजपा की उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आए थे, जिसे राजनीतिक हलकों में एक बड़ा सबक माना गया. इसके बाद विपक्ष लगातार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है. लेकिन शाह-योगी की इस ताजा बैठक ने उन सभी अटकलों पर पूरी तरह विराम लगा दिया है.

योगी-शाह की मुलाकात के क्या हैं मायने

इस मुलाकात ने साफ कर दिया है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व पूरी तरह से एक मेज पर है. पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और अमित शाह के साथ हुई इन बैठकों के बाद यह बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया है कि साल 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे और उनके काम के दम पर ही लड़ा जाएगा.

क्या है यूपी चुनाव 2027 के लिए बना नया प्लान?

सूत्रों के मुताबिक, इस सीक्रेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश को लेकर एक 'त्रिस्तरीय मेगा प्लान' तैयार किया गया है. हाल ही में हुए यूपी कैबिनेट विस्तार के बाद शाह ने सीएम योगी को पूरी तरह 'फ्री हैंड' दिया है. सपा के 'पीडीए' पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कार्ड को काटने के लिए भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडेय जैसे हेवीवेट नेताओं और गैर-यादव ओबीसी व दलित चेहरों को जमीन पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है. अयोध्या समेत पूरे सूबे में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को समय से पहले पूरा करना और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति को और आक्रामक बनाया रहा है.

दिल्ली में बैठस से तय हो गया लखनऊ का रास्ता

इस बैठक के ठीक बाद लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर मंत्रिपरिषद की बड़ी बैठक बुलाई गई, जो यह दशार्ती है कि दिल्ली में जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था, उसे जमीन पर उतारने का काम तुरंत शुरू कर दिया गया है. अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश देश की सत्ता का मुख्य रास्ता है, इसलिए 2027 में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

अयोध्या के नतीजों से जो डैमेज हुआ था, भाजपा उसे एक बड़े अवसर में बदलने जा रही है. अमित शाह की संगठनात्मक क्षमता और सीएम योगी आदित्यनाथ की बेदाग व सख्त छवि का यह कॉम्बिनेशन अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठबंधन के लिए एक अभेद्य चक्रव्यूह तैयार कर रहा है. विपक्ष जहां अभी सीट शेयरिंग और अंदरूनी खींचतान में उलझा है, वहीं भाजपा ने 2027 के लिए अपने सबसे बड़े सूरमाओं को मैदान में उतारकर शंखनाद कर दिया है.

लखनऊ-सीतापुर फोरलेन हाईवे होगा सिक्स लेन; 1000 करोड़ की लागत, 1 घंटे में पूरा होगा सफर

(जीएनएस)।

लखनऊः लखनऊ से सीतापुर तक की फोरलेन सड़क अब सिक्स लेन चौड़ी होगी. यह बख्शी का तालाब में आउटर रिंग रोड मोड़ से सिक्स लेन चौड़ाई शुरू हो जाएगी जो सीतापुर रोड पर टोल रोड समाप्त होने तक सिक्स लेन रहेगी.

फिलहाल लखनऊ से सीतापुर तक का सफर 2 घंटे का है, जो कि सिक्स लेन रोड होने के बाद 1 घंटे का रह जाएगा. अगले 3 महीने में सीतापुर रोड को सिक्स लेन करने का काम शुरू हो जाएगा और लगभग 1000 करोड़ रुपये का खर्च इस पर होने की संभावना है.

3 महीने में शुरू होगा निमार्णः महज डेढ़ साल में इस सिक्स लेन का काम पूरा कर लिया जाएगा. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को इस सड़क के चौड़ीकरण की घोषणा की थी. जिसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रतिनिधि व सेवानिवृत आईएएस अधिकारी

दिवाकर त्रिपाठी ने बताया कि जहां आउटर रिंग रोड सीतापुर रोड पर उतर रही है, यानी बक्शी का तालाब में एसआरजी इंजीनियरिंग कॉलेज के मोड़ पर, वहां से फोरलेन सड़क सिक्स लेन की जाएगी. यह चौड़ीकरण सीतापुर में टोल रोड की समाप्ति तक जारी रहेगा. लाखों लोगों को तोहफा; नैमिषारण्य धाम की राह भी होगी आसान

NHAI करेगा निर्माण, नहीं बढ़ेगा टोल टैक्सः दिवाकर त्रिपाठी ने बताया कि लंबे समय से सीतापुर रोड के चौड़ीकरण की मांग की जा रही थी, जिसको केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है. उन्होंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसका निर्माण करेगा. सड़क के दोनों ओर एक-एक लेन का चौड़ीकरण किया जाएगा. इसके साथ ही स्थानीय यातायात के लिए बेहतर सर्विस रोड भी बनाई जाएगी.

नैमिषारण्य धाम जाना होगा आसानः उन्होंने बताया कि सीतापुर तक का सफर आसान होगा और मात्र 1 घंटे में पूरा किया जाएगा. इस अतिरिक्त लेन की बढ़ोतरी के बावजूद आम जनता पर बोझ नहीं डाला जाएगा और टोल टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी. उन्होंने बताया कि लखनऊ-सीतापुर के बीच में इटौंजा, सिधौली, लहरपुर और खैराबाद आदि इलाकों को इससे बहुत लाभ होगा. इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए प्रसिद्ध नैमिषारण्य धाम जाना भी बेहद आसान हो जाएगा. उन्होंने बताया कि अगले डेढ़ साल में इसका निर्माण पूरा हो जाने की पूरी संभावना है.

कोई 140, कोई 180... पहले ही दिन कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दिखा रफ्तार का खेल, सड़क बना स्पीड टेस्ट ट्रैक

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे की शुरूआत हो चुकी है. लोकल-18 की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची और एक्सप्रेसवे पर सफर किया, तो वहां कई वाहन निर्धारित गति सीमा से कहीं ज्यादा रफ्तार में दौड़ते नजर आए.

(जीएनएस)।

कानपुरः कानपुर और लखनऊ के बीच सफर को आसान और तेज बनाने वाला कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे सोमवार से आम लोगों के लिए खोल दिया गया. पहले ही दिन इस एक्सप्रेसवे पर लोगों का उत्साह साफ दिखाई दिया, लेकिन कई वाहन चालकों ने इस उत्साह को रफ्तार के खेल में बदल दिया. लोकल-18 की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची और एक्सप्रेसवे पर सफर किया, तो वहां कई वाहन निर्धारित गति सीमा से कहीं ज्यादा रफ्तार में दौड़ते नजर आए.

कई वाहन निकले बहुत आगे

एक्सप्रेसवे पर सफर के दौरान हमारी गाड़ी की औसत रफ्तार करीब 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जो तय गति सीमा के भीतर थी. सड़क बेहद शानदार और सफर काफी स्मूथ था. लेकिन इसी दौरान कई वाहन चालक अपनी कारों को तेज रफ्तार में दौड़ाते दिखाई दिए. ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोगों के लिए यह एक्सप्रेसवे नहीं, बल्कि

स्पीड टेस्ट ट्रैक बन गया हो.

कोई 140, तो कोई 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार

ग्राउंड पर मौजूद रहने के दौरान जब मोबाइल एप्स और स्पीड ट्रैकिंग के जरिए आसपास चल रहे वाहनों की गति देखी गई, तो कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए. कुछ कारें 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थीं. कई वाहन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर दिखाई दिए, जबकि कुछ गाड़ियां 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ चुकी थीं.

इतना ही नहीं, कई ट्रक और अन्य कमर्शियल वाहन भी 120 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति में चलते दिखाई दिए. विशेषज्ञों का मानना है कि एक्सप्रेसवे की चौड़ी और बेहतर सड़कें अक्सर वाहन चालकों को तेज रफ्तार के लिए आकर्षित करती हैं, लेकिन यही तेज रफ्तार हादसों की सबसे बड़ी वजह भी बनती है. कुछ मिनट जल्दी पहुंचने की जल्दबाजी कई बार जिंदगी भर का नुकसान बन जाती है.

आखिर एक्सप्रेसवे पर कितनी है तय गति सीमा?

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों जैसे कार और एसयूवी के लिए अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है. वहीं कमर्शियल और भारी वाहनों के लिए यह सीमा 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है. इसके बावजूद पहले ही दिन कई वाहन चालक तय सीमा से काफी ऊपर गाड़ियां दौड़ाते नजर आए. एक्सप्रेसवे पर लगे एआई कैमरे और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचान प्रणाली ऐसे वाहनों पर लगातार नजर रख रही है और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है.

क्या बाइक, ई-रिक्शा और ऑटो नहीं चल सकेंगे?

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोपहिया और तीन पहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है. इसका मतलब है कि बाइक, स्कूटी, ई-रिक्शा, ऑटो, साइकिल और अन्य धीमी गति वाले वाहन इस एक्सप्रेसवे पर सफर नहीं कर सकेंगे. इन वाहनों को पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य वैकल्पिक मार्गों का ही इस्तेमाल करना होगा.

यह फैसला तेज रफ्तार वाहनों के बीच छोटे और धीमे वाहनों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है. कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे ने दोनों शहरों के बीच दूरी जरूर कम कर दी है, लेकिन इस नई सड़क पर सुरक्षित सफर की जिम्मेदारी अब वाहन चालकों की भी है. अगर रफ्तार पर नियंत्रण नहीं रखा गया, तो यह एक्सप्रेसवे सुविधा के साथ-साथ खतरे का कारण भी बन सकता है.

राष्ट्र प्रेरणा स्थल तक मेट्रो का विस्तार, गोमती के किनारे स्पोर्ट्स सिटी; योजना के बारे में जानिए

लखनऊ मेट्रो के विस्तार की परियोजना को हरी झंडी दे दी गई है। सरकार की ओर से सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी।

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश की राजधानी में मेट्रो विस्तार की परियोजना पर विचार किया जा रहा है। इस क्रम में राष्ट्र प्रेरणा स्थल तक मेट्रो विस्तार की योजना तैयार की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया था। इस स्थल तक अब लोग मेट्रो से यात्रा कर सकेंगे। यूपी सरकार के स्तर पर सोमवार को हुई बैठक में वसंत कुंज से राष्ट्र प्रेरणा स्थल तक मेट्रो विस्तार परियोजना पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। हालांकि, परियोजना के लिए आवश्यक बजट को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं होने की बात सामने आई है।

एलडीए से फंड की डिमांड

राष्ट्र प्रेरणा स्थल के प्रस्तावित एक्सटेंशन प्रोजेक्ट की लंबाई तीन किलोमीटर से अधिक होने का दावा किया जा रहा है। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रारंभिक आकलन के

अनुसार इस हिस्से के निर्माण पर करीब 500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसके लिए मेट्रो कॉरपोरेशन ने लखनऊ विकास प्राधिकरण से वित्तीय सहयोग मांगा है। अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल को प्रदेश और देश के प्रमुख पर्यटन एवं प्रेरणात्मक स्थलों के रूप में विकसित किया जा रहा है।

अधिकारियों का दावा है कि मेट्रो कनेक्टिविटी मिलने से बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों, विद्यार्थियों और आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। सड़क यातायात पर दबाव भी कम होगा। राशि काफी बड़ी होने के कारण एलडीए ने अभी इस पर अंतिम सहमति नहीं दी है।

स्पोर्ट्स कॉरिडोर का निर्माण

राजधानी लखनऊ को विश्वस्तरीय लुक देने के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इसको लेकर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के आसपास गोमती के 7.5 किलोमीटर लंबे तटीय क्षेत्र को विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इसके लिए निर्मल गोमती स्पोर्ट्स कॉरिडोर, वाटरफ्रंट रीजुवनेशन और सिटी फॉरेस्ट के विकास की योजना है। यहां पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए भी अलग से ट्रैक का निर्माण किया जाएगा।

योजना का उद्देश्य गोमती किनारे खेल, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, मनोरंजन एवं व्यावसायिक गतिविधियों का एकीकृत केंद्र विकसित करना है। यूपी एससीआर के तहत इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्तावित योजना के तहत गोमती नदी के किनारे रिवर प्रोमेनेड, इनडोर एवं आउटडोर स्पोर्ट्स एरिना, कम्युनिटी स्पोर्ट्स क्लब और मनोरंजन गतिविधियों के लिए विशेष क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।

'आतंकी के बेडरूम का लोकेशन फीड कर देंगे, ब्रह्मोस मिसाइल सीधे खटिया तक पहुंचेगी', लखनऊ में बोले ब्रजेश पाठक

लखनऊ के KGMU के दीक्षांत समारोह में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि लखनऊ में बन रही ब्रह्मोस मिसाइल कंप्यूटर में लक्ष्य फीड करते ही आतंकियों की 'खटिया' तक पहुंचकर सटीक वार करती है।

(जीएनएस)।

लखनऊः किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के 22वें दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रक्षा क्षेत्र में लखनऊ की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कभी लखनऊ की पहचान सिर्फ 'मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं' से होती थी, लेकिन अब यही शहर देश की सबसे आधुनिक मिसाइलों में शामिल ब्रह्मोस के निर्माण का केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि यह मिसाइल इतनी सटीक है कि कंप्यूटर में लक्ष्य फीड करने के बाद सीधे वहीं जाकर वार करती है और निशाना चूकने का सवाल ही नहीं उठता।

दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने की, जबकि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में कुल 1707 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। वहीं 20 विद्यार्थियों को 54 विभिन्न मेडल देकर सम्मानित किया गया।

'लखनऊ में बन रही ब्रह्मोस'

अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सादगी की मिसाल हैं और उनके कंधों पर देश की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भी हो रहा है।

पहले लखनऊ के बारे में कहा जाता था- मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। किसी ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि इसी लखनऊ में ब्रह्मोस जैसी आधुनिक मिसाइल बनेगी। यह ऐसी मिसाइल नहीं है कि निशाना लगाकर दागना पड़े। कंप्यूटर में फीड कर देंगे कि किस बेडरूम में कहां आतंकवादी हैं, तो सीधे वहीं जाकर खटिया पर लगेगी। दाएं-बाएं नहीं जाएगी, निशाना चूकने का सवाल ही नहीं है।

1707 विद्यार्थियों को मिली डिग्री

केजीएमयू के 22वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने की, जबकि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में कुल 1707 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। वहीं 20 विद्यार्थियों को 54 विभिन्न मेडल देकर सम्मानित किया गया। एमबीबीएस की छात्रा दीप्ति शर्मा ने सबसे अधिक 16 पदक अपने नाम किए, जिनमें प्रतिष्ठित हीवेट और चांसलर मेडल भी शामिल रहे।

राजनाथ सिंह का बयान

समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी चिकित्सक की असली पहचान केवल उसकी डिग्री या ज्ञान नहीं, बल्कि मरीज के प्रति उसका व्यवहार, संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण होता है। उन्होंने कहा कि मरीज दवा से पहले डॉक्टर के स्नेह और आत्मीयता को याद रखता है, इसलिए इलाज में 'हीलिंग टच' की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।

नरोत्तम ने कहा- दतिया में चुनाव प्रचार करूंगा

उन्होंने कहा कि कई मरीज डॉक्टर को सफेद कोट में देखकर ही घबरा जाते हैं, जिसे 'व्हाइट कोट सिंड्रोम' कहा जाता है। इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। नए डॉक्टरों से उन्होंने आ'ान किया कि वे सेवा भाव के साथ चिकित्सा पेशे को अपनाएं और हर मरीज के साथ समान व्यवहार करें। उन्होंने यह भी कहा कि मरीज की पूरी बात धैर्य से सुनना चाहिए, क्योंकि कई बार बीमारी का सही सुराग उसी की बातों में छिपा होता है।

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का स्वागत करेगा सोनीपत, 800 छात्र बनेंगे इस ऐतिहासिक पल के गवाह

(जीएनएस)।

सोनीपत। देश के परिवहन इतिहास में 17 जुलाई का दिन बेहद खास होने जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।

इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए चार स्टेशनों पर 800 विद्यार्थी अलग-अलग स्टेशनों पर मौजूद रहेंगे और हाइड्रोजन ट्रेन की खूबियां जानेंगे।

कार्यक्रम को लेकर सोनीपत जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए उपायुक्त नेहा सिंह ने लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की।

प्रशासन का पूरा ध्यान कार्यक्रम को भव्य और तकनीक-अनुकूल बनाने पर है। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा गोहाना, लाठ और मोहाना स्टेशनों पर भी विशेष प्रबंध किए गए हैं, जहां लोग और विद्यार्थी इस ऐतिहासिक पल का लाइव टेलीकास्ट देख सकेंगे।

डीसी नेहा सिंह ने कार्यक्रम की गंभीरता को देखते हुए गोहाना एसडीएम को गोहाना, खरखौदा एसडीएम को लाठ और गन्नौर एसडीएम को मोहाना स्टेशनों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों को खुद मौके पर जाकर निरीक्षण करने और तैयारियों में कोई कमी न छोड़ने के निर्देश दिए हैं।

विद्यार्थियों की रहेगी बड़ी भागीदारी

कार्यक्रम के आयोजन में युवाओं और विद्यार्थियों को विशेष रूप से जोड़ा जा रहा है। प्रत्येक स्टेशन पर विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे डीक्रस्ट मुरथल, बीपीएस खानपुर कलां, बीपीएल पालिटेक्निक और हिंदू कॉलेज के 200-200 विद्यार्थी सोनीपत, गोहाना, लाठ और मोहाना रेलवे स्टेशनों पर मौजूद रहेंगे।

जिला प्रशासन ने इन विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित यातायात (रोडवेज बसें), बैठने की व्यवस्था, पेयजल और रिफ्रेशमेंट के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।

सुरक्षा व बुनियादी सुविधाओं पर की चर्चा

बैठक में डीसी नेहा सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक रूट प्लान और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर भी अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा, एसडीएम सोनीपत सुभाष चंद्र, एसडीएम खरखौदा अमित कुमार, पीजीआइ खानपुर के अतिरिक्त निदेशक सुरेंद्र दून, सीटीएम सिमरन, जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया, जीएम रोडवेज संजय कुमार, मोटर वाहन अधिकारी सचिन कुमार तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

PRGI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

ईरान द्वारा अपने सुप्रीमलीडर की हत्या के बदले ट्रंप की हत्या की साजिश

इजरायल ने अमेरिका के साथ ऐसी नई जानकारी देने का दावा किया है, जिसमें ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। अमेरिकी मीडिया में यह दावा किया गया है।

ट्रंप इस पर भड़क गए और अपना आपा खो बैठे हैं। अमेरिका का प्रतिष्ठित समाचार पत्र द वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट छपी है, जिसके मुताबिक इजरायल ने अमेरिका को बताया है कि उसके पास खुफिया रिपोर्ट है।

खुफिया जानकारी है जिसके अनुसार तेहरान ट्रंप की हत्या की नई योजना बना रहा है। मोसाद ने ये इंटेल शेयर की है और ट्रंप से कहा है कि वे ईरान के टारगेट नंबर वन पर है। इसका नतीजा यह हुआ कि नाटो के समिट के बाद ट्रंप ने डर कर अपना नया एयर फोर्स वन बदल डाला और अमेरिका से पूरा एयर फोर्स वन मंगवाया और उसमें वापस अमेरिका पहुंचे। उधर ट्रंप ने दावा किया कि अगर ईरान उनकी हत्या करने में सफल होता है तो उन्होंने पहले ही एक आदेश दे रखा है कि अगर ईरान अमेरिका पर हमला करता है, जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा ऐसा जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि 1000 मिसाइलें ईरान को अपने निशाने पर लिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान उनकी हत्या करने में सफल होता है तो उन्होंने पहले से ही एक आदेश दे रखा है। न्यूयार्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि इस आदेश के मुताबिक ईरान पर इतना बड़ा जवाबी हमला करे जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। सवाल उठता है कि क्या ट्रंप ऐसा कोई आदेश दे भी सकते हैं या फिर इतिहास में किसी नेता ने ऐसा आदेश दिया था। अमेरिकी संविधान के तहत कोई भी राष्ट्रपति ऐसा आदेश नहीं छोड़ सकता कि उसकी मौत के बाद अपने आप किसी देश पर हमला कर दिया जाए। किसी भी बड़े सैन्य अभियान का फैसला उस समय जो राष्ट्रपति होगा वही तय करेगा। क्योंकि कमांडर इन चीफ के आदेश पर ही अमेरिकी सेना ऐसा वुछ कर सकती है। ट्रंप का यह बयान सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि अमेरिकी जनता के लिए भी एक राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। एक तरफ वह अपने समर्थकों के सामने यह छवि बनाना चाहते हैं कि वह निडर हैं और सख्त नेता हैं जो किसी भी धमकी के आगे नहीं झुवेंगे, दूसरी तरफ ईरान को यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो जवाब पूरे देश को मिलेगा। सभी जानते हैं कि इजरायल अमेरिका- ईरान के शांति-वार्ता से परेशान है और इसे हर हालत में तोड़ना चाहता है। वह ट्रंप कितने बहादुर हैं यह भी जानती है। इससे बेहतर क्या हो सकता है कि यह खबर चला दो कि आप ईरान के टारगेट नंबर वन हैं। इससे ट्रंप मजबूरन ईरान पर हमला कर देंगे और एक बार फिर युद्ध शुरू हो जाएगा। हुआ भी यही। अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए और ईरान ने भी जबर्दस्त जवाबी कार्रवाई कर दी। एक बार फिर मध्य-पूर्व जंग की आग में धकेल दिया गया। वैसे हम ट्रंप और नेतन्याहू से पूछना चाहते हैं कि जब आपने 28 फरवरी को अयातुल्ला अली खामेनेई और उनके लगभग पूरे परिवार को निशाना बनाया था, जिसमें उनकी 14 महीने की पोती भी शामिल थी, 40 से अधिक टॉप के मिलिट्री कमांडरों को निशाना बनाया था तब आपको यह ख्याल नहीं आया था कि ईरान भी ऐसा कर सकता है और अपने सुप्रीम लीडर की हत्या का बदला ले सकता है? अब जब अपने पर पड़ी तो आप को नानी याद आ गई। वैसे भी इजरायल के मंत्री ने खुलेआम ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई की हत्या करने की खुली धमकी दी थी। शहीद अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में आपने देखा होगा कि किस तरह करोड़ों लोगों ने अपने रहबर की हत्या का बदला लेने की कसम खाई थी। ईरान आपसे बदला ले सकता है और ले भी रहा है पर इस तरह नहीं जैसे नेतन्याहू और मोसाद आपको बेववूफ बनाकर अपने हित साध रहा है।

अमेरिकी जांच के बीच भारत की पॉलिसी में बड़ा चेंज, ऐसे आयात पर लगा दी रोक

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः भारत ने अपनी विदेश व्यापार नीति (FTP) में बदलाव किया है। मकसद यह है कि जबरन मजदूरी से बने या तैयार किए गए सामान के आयात पर रोक लगाई जा सके। यह कदम उसके व्यापार नियमों को अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों के अनुरूप बनाता है। इससे अमेरिका की ओर से चल रही व्यापार जांच में उठाए गए मुद्दों को हल करने में मदद मिल सकती है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने FTP, 2023 में एक नया प्रावधान जोड़ा है। ऐसा करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। यह केंद्र सरकार को अलग-अलग नोटिफिकेशन के जरिए ऐसे सामान के आयात पर रोक लगाने का अधिकार देता है जिनके बारे में पता चलता है कि उन्हें पूरी तरह या आंशिक रूप से जबरन मजदूरी से बनाया गया है। नए नियम ऑफिशियल गजट में प्रकाशित होने के 30 दिन बाद लागू होंगे।

अमेरिकी जांच के बीच उठाया गया कदम

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत उन कई देशों में शामिल है जिन पर अमेरिका 12.5% तक का अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है।

अमेरिका यह जांच कर रहा है कि क्या उसके व्यापारिक साझेदारों के पास जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय हैं।

अभी अमेरिका को होने वाले ज्यादातर भारतीय निर्यात पर 10% टैरिफ लगता है। जबकि वॉशिंगटन

अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता से जुड़ी अलग-अलग जांच भी कर रहा है।

नए जोड़े गए पैराग्राफ 2.20इ के तहत जबरन मजदूरी का इस्तेमाल करके पूरी तरह या आंशिक रूप से बनाए गए सामान के आयात पर रोक है। केंद्र सरकार जांच के नतीजों या अपनी समझ से उचित अन्य जानकारी के आधार पर आयात प्रतिबंधों के लिए खास सामान की पहचान कर सकती है।

जोड़ी गई है नई परिभाषा

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि DGFT इस बात की जांच करेगा कि क्या आयातित सामान जबरन मजदूरी से बनाया गया था। अगर सबूत मिलते हैं तो वह सरकार से उन उत्पादों के आयात पर रोक लगाने की सिफारिश कर सकता है। जांच की प्रक्रिया 'हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स, 2023' में बताई गई प्रक्रियाओं के अनुसार होगी।

नोटिफिकेशन में एफटीपी के चैप्टर 11 के तहत 'जबरन मजदूरी' की एक नई परिभाषा भी जोड़ी गई है। इसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन (ILO) के 'फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, 1930 (नंबर 29)' में दी गई परिभाषा को अपनाया गया है।

जबरन मजदूरी का मतलब क्या है?

नोटिफिकेशन के अनुसार, जबरन मजदूरी का मतलब है -'कोई भी ऐसा काम या सेवा जो किसी व्यक्ति से किसी सजा के डर से जबरदस्ती कराई जाए और जिसके लिए उस व्यक्ति ने स्वेच्छा से अपनी सहमति न दी हो।'

DGFT ने कहा कि ये बदलाव भारत के व्यापार नीति ढांचे को मजबूत करते हैं। इससे सरकार जबरन मजदूरी से जुड़े आयात पर रोक लगा सकती है। साथ ही FTP को क्छड कन्वेंशन के अनुरूप बना सकती है। यह नोटिफिकेशन वाणिज्य और उद्योग मंत्री की मंजूरी से 'विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992' के तहत जारी किया गया था।

सिंधु जल समझौताः भारत के कड़े तेवरों से पाकिस्तान में खलबली, पानी की जंग का अतीत; वर्तमान और भविष्य क्या?

(जीएनएस)।

नई दिल्ली। कई दशकों तक भारत की उदारता का पानी पीने और उसी पानी के दम पर आतंकवाद की फसल उगाने वाले पाकिस्तान के पापों का घड़ा अब पूरी तरह भर चुका है। भारत के कड़े तेवरों और सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डालने के फैसले ने कंगाल और नापाक पड़ोसी पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ दी है।

इस बात को ऐसे समझिए कि कभी पानी के सहारे हेकड़ी दिखाने वाला इस्लामाबाद आज बूंद-बूंद पानी और पाई-पाई के लिए तड़पने को मजबूर है। 'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते' की नीति के तहत भारत ने जो रणनीतिक चक्रव्यूह रचा है, उसने पाकिस्तान को अपनी बदहाली और बेबसी पर आंसू बहाने को मजबूर कर दिया है।

ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि भारत का इस कड़े रुख से सिंधु जल समझौते का अतीत, वर्तमान और भविष्य क्या और कैसा होगा? आइए हम आपको बताते हैं।

पहले सिंधु जल समझौते के वर्तमान को समझते हैं

बात वर्तमान की करें तो पिछले छह दशकों से जिस सिंधु जल समझौते को दुनिया की सबसे सफल राजनयिक जीतों में गिना जाता था, आज वह इतिहास के सबसे बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। यह वही समझौता है जो भारत-पाकिस्तान के बीच कई युद्धों, आतंकी हमलों और दशकों की कड़वाहट के बाद भी कभी नहीं टूटा। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है।

इसका बड़ा कारण अप्रैल 2025 में हुआ पहलगाम आतंकी हमला है। इसके बाद भारत ने सख्त एक्शन लेते हुए इस समझौते को स्थगित कर दिया है। साफ शब्दों में कहे तो नई दिल्ली ने आतंकियों के पनाहगाह पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने और पानी को एक 'रणनीतिक हथियार' के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी तेज कर दी।

इस बार पाकिस्तान की किरकिरी क्यों हो रही है?

इस बात को ऐसे समझिए कि पाकिस्तान हमेशा से भारत के पानी पर मौज करता आया है, लेकिन अब भारत ने जमीनी स्तर पर गेम बदल दिया है। इसी कारण पहले से कंगाल पाकिस्तान अब बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहा है। खैर, नापाक पड़ोसी के चिंता का विषय केवल यही नहीं है।

इसके अलावा पाकिस्तान की चिंता का विषय चेनाब-ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट भी है। इसको ऐसे समझिए कि भारत हिमाचल प्रदेश में 8.7 किलोमीटर लंबी एक टनल बनाने जा रहा है। इसके जरिए चेनाब की सहायक नदी 'चंद्र नदी' के पानी को मोड़कर ब्यास बेसिन में लाया जाएगा। यानी जो पानी बहकर पाकिस्तान जाता था, उसे भारत अपने इस्तेमाल में लेगा।

पश्चिमी नदियों पर ताबड़तोड़ प्रोजेक्ट्स

भारत ने सिंधु, झेलम और चेनाब (पश्चिमी नदियां) पर जलविद्युत और सिंचाई परियोजनाओं को युद्धस्तर पर तेज कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान ने जब इस पर आपत्ति जताई और मध्यस्थता अदालत से भारत के खिलाफ फैसले दिलवाए, तो भारत ने साफ कह दिया कि हम ऐसी किसी 'गैर-कानूनी' अदालत को नहीं मानते। फलस्वरूप पाकिस्तान रोता रह गया और भारत अपने काम में लगा रहा।

इतिहास की वो 'उदारता'

अच्छा, अब इस बात को समझने के लिए भारत का यह कदम कितना बड़ा है, हमें 1947 के दौर में जाना होगा और इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। शुरूआत से समझाएं तो जब भारत और पाकिस्तान बंटा, तो नहरों को नियंत्रित करने वाले हेडवर्क्स भारत में रह गए, जबकि लाखों एकड़ उपजाऊ जमीन और नहरों का जाल पाकिस्तान में चला गया।

इसके बाद अप्रैल 1948 में जब अस्थायी समझौता खत्म हुआ, तो पूर्वी पंजाब सरकार ने पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया। पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। हालांकि, तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के बाद पानी बहाल कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान को समझ आ गया कि उसकी लाइफलाइन भारत के हाथ में है।

9 साल की बातचीत और 'एकतरफा' समझौता

इसके बाद आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने सिंधु जल समझौते पर दस्तखत किए।

कैसा था यह अजीबोगरीब समझौता?

नदी का प्रकार नदियां पानी का हिस्सा (वार्षिक) भारत का नियंत्रण पाकिस्तान का नियंत्रण

पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलुज लगभग 33 MAF (20%) पूर्ण अधिकार (भारत अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है) कोई अधिकार नहीं

पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब लगभग 135 टअऋ (80%) सीमित अधिकार (केवल घरेलू उपयोग, बिजली और सीमित सिंचाई) मुख्य अधिकार (बिना रोक-टोक इस्तेमाल)

इस समझौते की अजीब बात पर रौशनी डालें तो भारत ने न केवल पाकिस्तान को 80% पानी दे दिया, बल्कि पाकिस्तान में नहरें और बुनियादी ढांचा बनाने के लिए अपनी जेब से 6.2 करोड़ पाउंड (जो कि वर्तमान समय के अनुसार 79.47 करोड़ से 79.80 करोड़ रुपये) भी दिए। यह समझौता इसलिएअ भी अजीब था, क्योंकि वैश्विक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऊपर बसा देश नीचे वाले देश को पानी भी दे और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के पैसे भी दे।

'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते' की नीति

ध्यान देने वाली बात यह है कि दशकों तक भारत ने इस असमान समझौते को निभाया। कारगिल युद्ध और मुंबई हमलों के बाद भी भारत ने पानी नहीं रोका। लेकिन आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान के लिए भारत का सब्र अब टूट चुका है। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया कि अब पानी को राजनीति से अलग नहीं रखा जाएगा। भारत ने समझौते को 'ठंडे बस्ते' में डाल दिया।

अदालती जंग में भी पाकिस्तान पस्त

पाकिस्तान ने इस मामले को लेकर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का दरवाजा खटखटाया। मई 2026 में इस अदालत ने पाकिस्तान के पक्ष में फैसला देने की कोशिश की, लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया कि हम इस एकतरफा फैसले को कचरे के डिब्बे में फेंकते हैं।

गौतम गंभीर और अजीत अगरकर में टकराव? सरेआम सामने आकर दिनेश कार्तिक ने किया बड़ा खुलासा

(जीएनएस)।

इंग्लैंड और आयरलैंड में टीम इंडिया की टी20 सीरीज में हार के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। दिनेश कार्तिक ने एक ऐसा बयान दिया है, जो भारतीय क्रिकेट में भूचाल ला सकता है। कार्तिक ने कोच गौतम गंभीर और चीफ सलेक्टर अजीत अगरकर के बीच टकराव की बात कही है।

स्काई स्पोर्ट्स के पॉडकास्ट पर बात करते हुए दिनेश कार्तिक ने कहा कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की सोच अलग-अलग है। दोनों के बीच कुछ खींचतान है। अगरकर एक ऐसी टीम बनाना चाहते हैं, जिसे लेकर लंबे समय की प्लानिंग की जा सके।

दिनेश कार्तिक का तगड़ा खुलासा

कार्तिक ने कहा कि गौतम गंभीर के साथ ऐसा नहीं है, वह अपना नाम खराब होने से भी बचना चाहते हैं। गौतम गंभीर चाहते हैं कि वह हर सीरीज में जीत दर्ज करने वाली टीम बनाएं। कार्तिक ने कहा कि कोच गौतम गंभीर का मानना है कि टीम की हार होने पर कप्तान के अलावा कोच का नाम भी खराब होता है।

कार्तिक ने कहा कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ को देखा जाए, वहां कितने प्लेयर हैं। अगर कोई खिलाड़ी दो गेम खराब खेलता है, तो वह सोचता है कि मुझे कोई रिप्लेस कर देगा। इसके बावजूद यह (आयरलैंड, इंग्लैंड रिजल्ट) होता है। यह निश्चित तौर पर एक ऐसी स्थिति है, जिसके बारे में भारत को अब सोचना पड़ेगा और जल्दी चीजों को ठीक भी करना पड़ेगा।

इंग्लैंड में फेल हुए सभी कॉम्बिनेशन

गौरतलब है कि आयरलैंड और इंग्लैंड दोनों में भारतीय टीम बैटिंग और गेंदबाजी दोनों में फ्लॉप रही। ऐसा नहीं है कि टीम में जीत दिलाने वाले खिलाड़ी नहीं थे। वहां की कंडीशंस में भारतीय टीम के प्लेयर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

5 साल के वैभव सूर्यवंशी को भी तीन मैचों में मौका दिया गया था लेकिन वह भी रन बनाने में नाकाम रहे। भारत के लिए श्रेयस अय्यर ने रन बनाए थे। अन्य सभी प्लेयर्स फ्लॉप हो गए लेकिन यही खिलाड़ी आईपीएल में स्टार थे। इसके बाद से गौतम गंभीर, अजीत अगरकर सभी आलोचकों के निशाने पर हैं।

सड़क पर लाचार होकर भटक रहीं ये फेमस एक्ट्रेस, बिना पैसों के मां-बेटी की हुई ऐसी हालत, बेबसी देख लोग हुए परेशान

(जीएनएस)।

तेलुगू फिल्मों की फेमस एक्ट्रेस पावला श्यामला पिछले तीन दशकों से लोगों को एंटरटेन कर रही हैं। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर काम किया है और लोगों ने उनकी एक्टिंग की हमेशा तारीफ भी की है। फिलहाल वह गंभीर रूप से बीमार हैं और पैसों की कमी से भी परेशान हैं। आर्थिक तंगी के चलते वह एक लाचार औरत की तरह सड़कों पर भटक रही हैं।

पावला श्यामला क्यों दर-दर भटक रही हैं?

आपको बता दें कि पावला श्यामला ने सिल्वर स्क्रीन पर एक मां, सास और पड़ोसी के रूप में अपनी नैचुरल एक्टिंग से लोगों के दिल में जगह बनाई है लेकिन अब उनकी निजी जिंदगी की हालत खराब हो गई है। उनके पास न तो पैसे हैं और न ही कोई काम। आर्थिक तंगी के अलावा वह गंभीर शारीरिक समस्याओं से भी जूझ रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं एक्ट्रेस की बेटी की हालत भी काफी चिंताजनक है।

गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं पावला और उनकी बेटी

जानकारी के अनुसार एक्ट्रेस पावला श्यामला को 'मां' एसोसिएशन के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री के कुछ सेलेब्स और डोनर पहले ही फाइनेंशियली सपोर्ट कर चुके हैं। फिल्म सोर्स के मुताबिक सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने भी एक्ट्रेस ते मेडिकल खर्च और रोजाना की जरूरतों के लिए हर महीने 10,000 रुपये देने का इंतजाम किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक्ट्रेस पावला अपने ट्रीटमेंट के लिए अस्पाल पहुंची थीं लेकिन मेडिकल खर्च के लिए पैसे न होने की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा था।

अनजान लोगों ने पावला को पहुंचाया अस्पताल

-वहीं कार ड्राइवर ने पावला को बीच सड़क पर ही छोड़ दिया था। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने एक्ट्रेस को सड़क पर अनाथ समझकर एक चैरिटी को सौंप दिया था।

अब एक बार फिर कुछ अनजान लोगों ने हैदराबाद के एर्रागड्डा में गवर्नमेंट चेस्ट हॉस्पिटल के कैंपस में पावला श्यामला और उनकी बेटी माधवी को छोड़ दिया है। हॉस्पिटल के स्टाफ ने जब उन्हें बेबस हालत में देखा, तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई।

'शोएब अख्तर-आसिफ भारत ड्रग्स लेकर आते थे',कौन हैं आरवीएस मणि? बोले- वूल्मर भी तस्करी के चलते मरा

(जीएनएस)।

पाकिस्तानी क्रिकेटरों को लेकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पूर्व सेक्रेटरी आरवीएस मणि ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसने न्यूज रूम से लेकर सोशल मीडिया तक पर सनसनी पैदा कर दी है। अठकके पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि 'पाकिस्तान के कुछ लोकोप्रिय क्रिकेटर जब इंडिया खेलने आते थे तो वो अपने साथ ड्रग्स लेकर आते थे, उन्होंने बकायदा इस मामले में शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ का नाम लिया।'

उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 'पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ जैसे खिलाड़ी हर दौरे पर भारत में ड्रग्स की तस्करी करते थे। एक मामले में, वे घबरा गए और उन्होंने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया था।'

'उनके कोच बॉब वूल्मर, जिन्होंने इस तस्करी का खुलासा किया था, इसलिए ही मारे गए थे। 30% आतंकी हमलों के लिए इसी ड्रग मनी से ही फंडिंग की गई थी और इन सबके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ था।'

'शोएब-आसिफ ड्रग्स लेकर आते थे', आरवीएस मणि का खुलासा

स्मिता प्रकाश को दिए इंटरव्यू में आरवीएस मणि ने खुले तौर पर कहा कि 'पाकिस्तान हाई कमिश्नर के सामने शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ दोनों ने अपना जुर्म कबूला था और कहा था कि वो ड्रग्स लेकर आए हैं, उनके इस कबूलनामे के बाद उन्हें वापस भेज दिया गया था।'

शोएब-आमिर खुद करते थे ड्रग्स का इस्तेमाल?

जब स्मिता प्रकाश ने पूछा कि शोएब-आमिर ने तो कहा था कि ये उनके निजी प्रयोग के लिए है? तो इस पर आरवीएस मणि ने कहा कि 'ये सारी कोरी बातें हैं, वो ड्रग्स की तस्करी करते थे और वहीं नहीं जब पाकिस्तान का कोई प्रतिनिधिमंडल, क्रिकेट टीम या और भी कोई इंडिया आता था तो ड्रग्स की तस्करी होती थी।'

बॉब वूल्मर की मौत भी ड्रग्स के चलते ही हुईः आरवीएस मणि

'इस बात का विरोध पाकिस्तान टीम के इंग्लिश कोच बॉब वूल्मर ने किया था और इसी के चलते उनकी मौत हुई थी हालांकि बॉब वूल्मर की मौत की जांच कई जांच एजेसिंयों ने की थी लेकिन आज तक किसी भी रिपोर्ट में इस तरह की बातें सामने नहीं आई हैं। उन्होंने दावा किया कि आतंकवाद की फंडिंग भी ड्रग्स तस्करी से ही है।'

कौन हैं आरवीएस मणि?

आपको बता दें कि आरवीएस मणि का पूरा नाम रामास्वामी वेंकटा सुब्रा मणि है। 29 अक्टूबर 1959 को जन्मे आरवीएस मणि पूर्व सिविल सेवक, लेखक और विजिटिंग प्रोफेसर हैं। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस के सदस्य के तौर पर, उन्होंने गृह मंत्रालय (MHA) के आंतरिक सुरक्षा विभाग में अंडर सेक्रेटरी और बाद में कपड़ा मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी (वित्त) के रूप में काम किया है।

इशरत जहां एनकाउंटर मामले में किया था बड़ा खुलासा

उन्हें मुख्य रूप से 2004 के इशरत जहां एनकाउंटर मामले में व्हिसलब्लोअर के तौर पर जाना जाता है। वे वही अधिकारी थे जिन्होंने इस मामले में 6 अगस्त 2009 और 30 सितंबर 2009 को दाखिल दो हलफनामों पर हस्ताक्षर किए थे। पहले हलफनामे में कहा गया था कि 'मारे गए चारों लोग आतंकवादी थे', जबकि दूसरे हलफनामे में इसके उलट बात कही गई और साफ सबूतों की कमी की ओर इशारा किया गया।

पीएम मोदी जनता की बात सुनें', वांगचुक बोले-डॉक्टर-इंजीनियर भी नकल से बनेंगे तो देश कैसे बढ़ेगा?

जंतर-मंतर पर नीट-यूजी पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने परीक्षा सुधार, संसद में चर्चा और प्रधानमंत्री मोदी से जनता की आवाज सुनने की अपील की।

(जीएनएस)।

जंतर मंतर पर इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यह प्रदर्शन नीट- यूजी के प्रश्न पत्रों के लीक होने के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहा है। इस प्रदर्शन में कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल हैं। वह 17 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं।

इस बीच इंडियन एक्सप्रेस हिंदी से बात करते हुए वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जनता की आवाज सुनने का आग्रह किया। इसके साथ ही सभी दलों के नेताओं से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की।

सवालः परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए क्या किसी एक व्यक्ति के इस्तीफे से यह समस्या हल हो जाएगी?

जवाबः बिलकुल नहीं, लेकिन इससे जवाबदेही का रास्ता जरूर खुलेगा। जब तक सरकार जवाबदेही तय नहीं करती, इस तरह की मनमानी चलती रहेगी। यह सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर ही नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समाज पर कलंक है। अगर परीक्षा का पेपर लीक हो जाए तो आपको किस तरह का डॉक्टर मिलेगा? ऐसे डॉक्टर आपके बच्चों का इलाज करेंगे। नकल करके पास हुए इंजीनियर आपकी इमारतें बनाएंगे, जो ढह जाएंगी और जानें जाएंगी।

सबसे अहम बात यह है कि आज देश में ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं है। सब कुछ बेईमानी पर चलता है। परीक्षा के प्रश्नपत्रों से लेकर वोटों तक, सब कुछ बिकता है। इस तरह कोई देश प्रगति कैसे कर सकता है? विकसित राष्ट्र बनने की बात तो दूर, हम इस वैश्विक गांव का सामना कैसे कर पाएंगे?

सवालः आज आपकी भूख हड़ताल का 16वां दिन है। क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने आपसे कोई संपर्क किया है?

जवाबः नहीं। इसलिए, अब हमारा प्रयास है कि हम अपनी आवाज को और बुलंद करें ताकि वह उन तक पहुंच सके। अगर वह उन तक नहीं पहुंची है, तो यह केवल सरकार की गलती नहीं है, बल्कि इस देश की जनता की भी गलती है जिन्होंने इसे इतना बुलंद करने में मदद नहीं की कि इसे एक गंभीर मुद्दा माना जा सके। क्या आप तब तक अपनी आवाज नहीं उठाएंगे जब तक आप अकेले न हों और आपके साथ कोई न हो? अगर जनता सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज उठाएगी, तो सरकार के पास इसे सुलझाने के लिए बातचीत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।

'एथेनॉल को दोष मत दो', यूट्यूबर सौरव जोशी की मर्सिडीज के माइलेज वाले दावे की नितिन गडकरी ने खोली पोल,क्या कहा?

(जीएनएस)। देश में इन दिनों एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी E20 फ्यूल को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक एक नई बहस छिड़ गई है। हाल ही में देश के सबसे बड़े यूट्यूबर सौरव जोशी ने दावा किया कि E20 पेट्रोल की वजह से उनकी लग्जरी मर्सिडीज-बेंज कार का माइलेज अचानक बहुत कम हो गया है।

मामला बढ़ते ही खुद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मैदान में उतर आए हैं। गडकरी ने साफ शब्दों में कहा है कि गाड़ी में कोई भी खराबी आने पर आंख मूंदकर एथेनॉल को दोष देना बिल्कुल गलत है।

सौरव जोशी ने अपने व्लॉग में दावा किया था कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से उनकी मर्सिडीज कार का माइलेज काफी गिर गया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग एथेनॉल फ्यूल की क्वालिटी को लेकर सवाल उठाने लगे। लेकिन विवाद बढ़ता देख जर्मनी की दिग्गज कार कंपनी मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने तुरंत सामने आकर अपनी बात रखी।

कंपनी ने साफ किया कि उनकी सभी बीएस-6 (BS VI) पेट्रोल कारें E20 फ्यूल पर चलने के लिए पूरी तरह से फिट हैं। कंपनी की इस सफाई के बाद सौरव जोशी ने भी यू-टर्न ले लिया। उन्होंने अपनी बात सुधारते हुए माना कि उनकी कार का

माइलेज किसी फ्यूल की वजह से नहीं, बल्कि इंजन में आई एक तकनीकी खराबी के कारण गिरा था।

नितिन गडकरी बोले- 'हर खराबी का ठीकरा एथेनॉल पर मत फोड़ो'

इस पूरे मामले पर मंगलवार (14 जुलाई) को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने और पेट्रोल-डीजल के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए बायोफ्यूल का रोडमैप बहुत पहले ही साफ कर दिया गया था।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, "सरकार का वैकल्पिक ईंधन यानी बायोफ्यूल को अपनाने का प्लान शुरू से ही एकदम पारदर्शी रहा है। इस बारे में हर स्तर पर जनता को खुलकर जानकारी दी गई है। गाड़ियां भी एक मशीन हैं और किसी भी मशीन में कभी भी कोई मैकेनिकल खराबी आ सकती है। कोई भी तकनीक 100 प्रतिशत परफेक्ट नहीं होती। अगर आपकी गाड़ी में कोई समस्या आती है, तो डीलर के पास जाकर उसकी जांच कराएं और जरूरत पड़ने पर इंश्योरेंस का इस्तेमाल करें। गाड़ी की हर मैकेनिकल दिक्कत को जबरन एथेनॉल से जोड़ना ठीक नहीं है।"

क्या वाकई सुरक्षित है आपकी गाड़ी के लिए E20 फ्यूल? नितिन गडकरी ने समझाया

नितिन गडकरी ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। सरकार का रुख पूरी तरह साफ है कि नया E20 फ्यूल आज के वाहनों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। नितिन गडकरी के मुताबिक ई20 फ्यूल नए और पुराने दोनों तरह के वाहनों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और परखा हुआ है।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ लोग जानबूझकर इस ईंधन को लेकर भ्रम और डर का माहौल बना रहे हैं। यह आलोचना तथ्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक हित छिपे हुए हैं। इस नीति का सबसे बड़ा मकसद देश के करोड़ों रुपये बचाना और भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है।

इसलिए अगर आपकी कार या बाइक में माइलेज या परफॉर्मेंस की कोई दिक्कत आती है, तो सबसे पहले ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर जाकर मैकेनिक से गाड़ी की जांच करवाएं, न कि बिना सोचे-समझे ईंधन को इसका कसूरवार ठहराएं।

रहीमाबाद पुलिस ने बाइक चोरों को गिरफ्तार किया पांच बाईके बरामद

(जीएनएस)। मलिहाबाद लखनऊ। रहीमाबाद पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 5 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं।

बताते चले रहीमाबाद थाना के उ0नि0 रामसेवक राणा मय हमराही टीम गश्त कर रहे थे।मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि चनवा चौराहे पर मोटरसाइकिल चोरों को देखा गया मुखबीर की सूचना पर ग्राम सैदापुर मड़गांव में दबिश देकर आरोपी राकेश पुत्र राजकुमार 32 वर्ष, निवासी सैदापुर मजरा मड़गांव गदौरा थाना सण्डीला जनपद हरदोई को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 3 चोरी की बाइकें UP32GK3595 स्प्लेंडर, UP32W1354 पैशन, UP32CH3157 पैशन प्रो बरामद हुई।पूछताछ में

राकेश ने बताया कि वह अपने साथी मनीष पुत्र बेदव निवासी नबीपनाह थाना माल व सुनील पुत्र स्व0 छैदीलाल निवासी अटवारीडीहा थाना सण्डीला हरदोई के साथ मिलकर मोटरसाइकिल चोरी करता है।

आरोपी की निशानदेही पर दूसरे अभियुक्त सुनील पुत्र स्व0 छैदीलाल निवासी अटवारीडीहा थाना सण्डीला हरदोई को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर 2 और चोरी की बाइकें UP32GW3143 सीडी डीलक्स व UP32FD1960 डिस्कवर बरामद की गई। इस प्रकार कुल 05 अदद चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई।

तीसरा अभियुक्त मनीष पुत्र बेदव निवासी नबीपनाह थाना माल की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है। पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ थाना रहीमाबाद पर मु0अ0सं0 105/2026 धारा 317(2)/238/313(4) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

नौकरी से निकाले जाने के बाद कारोबारी से 12.5 किलो चांदी मांगने का आरोप

(जीएनएस)। लखनऊः राजधानी के चौक सराफा बाजार में फर्जी पार्टनरशिप के नाम पर करोड़ों के कारोबार में हिस्सेदारी का दावा कर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। एक चांदी कारोबारी ने अपने पूर्व अकाउंटेंट और उसके दो भाइयों पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर फर्म में 30 फीसदी हिस्सेदारी जताने और करीब 30 लाख रुपये कीमत की 12.5 किलो चांदी मांगने का आरोप लगाया है। कारोबारी का कहना है कि मांग ठुकराने पर उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

कारोबारी सिद्धार्थ उर्फ सिद्धू

सआदतगंज के रानी कटरा चौपटिया निवासी सिद्धार्थ कश्यप उर्फ सिद्धू के मुताबिक, करीब दो साल पहले उन्होंने एक युवक को 50 हजार रुपये मासिक वेतन पर अकाउंटेंट रखा था। कारोबार के हिसाब-किताब और वित्तीय लेन-देन की जिम्मेदारी उसी के पास थी। वर्ष 2025 में उसने कर्ज चुकाने की बात कहकर 1.80 लाख रुपये एडवांस भी लिए थे।

पीड़ित का आरोप है कि मार्च 2026 में आरोपी को प्रतिष्ठान के भीतर नशा करते हुए पकड़ा गया। इसके बाद उसका हिसाब कर नौकरी से हटा दिया गया। कारोबारी का कहना है कि इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर फर्जी पार्टनरशिप फर्म तैयार कर खुद को 30 प्रतिशत का साझेदार बताना शुरू कर दिया और साढ़े 12 किलो चांदी देने का दबाव बनाने लगा।

शिकायत के अनुसार, आरोपी अपने दो भाइयों के साथ लगातार रंगदारी वसूलने का दबाव बना रहा है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इससे कारोबारी और उसका परिवार भय के माहौल में है। चौक इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय ने बताया कि तहरीर मिल गई है। मामले की जांच चौकी प्रभारी नवकृष्ण द्विवेदी को सौंपी गई है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राहुल गांधी कहां हैं? नीट पेपर मुद्दे पर सरकार को घेरने वाली कांग्रेस ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट से क्यों बनाई दूरी

(जीएनएस)। देश की राजनीति में इन दिनों जंतर-मंतर पर चल रहे उखळ के प्रोटेस्ट का मुद्दा गरमाया हुआ है। सोनम वांगचुक NEET पेपर लीक और एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी को लेकर लगातार 17वें दिन भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

अब तक राजनीतिक रंग से दूर रहे इस प्रदर्शन में धीरे-धीरे अळढ, उढक ळव्टठ के नेताओं ने अपनी सॉलिडेरिटी दिखाई है। लेकिन राहुल गांधी उस मंच से कोसों दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे? सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर राहुल गांधी कहां हैं...?

यह सवाल इसलिए भी अहम बन जाता है क्योंकि जिस ट़एव्ळ पेपर लीक, परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी और सुधार को लेकर यूथ कांग्रेस महीनों से केंद्र सरकार पर हमलावर है। उसी मुद्दे को लेकर जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से कांग्रेस की दूरी राजनीतिक बहस का विषय बन गई है। क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सत्ता को जवाबदेह बनाना है।

मुद्दा वही, लेकिन मंच अलग... फिर कांग्रेस की दूरी क्यों?

बता दें कि कांग्रेस लगातार युवाओं का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि सिर्फ मुद्दा उठाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसमें खड़े दिखना भी उतना ही जरूरी होता है। यही कारण है कि राहुल गांधी की अनुपस्थिति अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुकी है।

यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी लगातार पेपर

लीक के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते रहे हैं। उन्होंने कोटा जाकर छात्रों से मुलाकात भी की, कांग्रेस युथ विंग देश भर में 'छात्रों की गूंज' अभियान शुरू किया। पेपर लिक के बाद से ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठाई।

यानी मुद्दा वही है, मांग भी लगभग वही है, लेकिन जब हजारों युवा बिना किसी राजनीतिक समर्थन के जंतर-मंतर पर एकजुट हैं, तब राहुल गांधी की गैरमौजूदगी कांग्रेस पर सवाल उठाती है।

राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि कांग्रेस की इस प्रदर्शन से दूरी एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। ऐसे में संभव है कि कांग्रेस किसी दूसरे संगठन के नेतृत्व वाले आंदोलन का हिस्सा बनने से बच रही हो। कांग्रेस का 'छात्रों की गूंज' अभियान इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस अभियान के जरिए पार्टी युवाओं के मुद्दों को भुनाने कोशिश कर रही है।

कांग्रेस की गौरमौजूदगी पर सोनम वांगचुक ने क्या कहा?

सोनम वांगचुक ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में विपक्षी दलों खासतौर पर कांग्रेस की अनुपस्थिति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस, युवाओं के इस आंदोलन में शामिल नहीं होता, तो यह उसकी छोटी सोच मानी जाएगी।

वांगचुक ने कहा कि यह मंच किसी राजनीतिक दल का नहीं है। यहां आने का मतलब किसी संगठन का समर्थन करना नहीं, बल्कि उन लाखों छात्रों के साथ खड़ा होना है जिनका भविष्य प्रभावित हुआ है। यदि विपक्ष इस आंदोलन से दूरी बनाए रखता है, तो जनता भविष्य में इसका जवाब दे सकती है।

सवाल सिर्फ राहुल गांधी का नहीं, INDIA गठबंधन की एकजुटता का भी है

सवाल केवल राहुल गांधी की तक सीमित नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि क्या देश के युवाओं से जुड़े इतने बड़े मुद्दे पर विपक्ष एक साझा मंच तैयार कर पाएगा? और क्या सरकार प्रदर्शनकारियों से संवाद शुरू करेगी? सबसे दिलचस्प बात यह है कि AAP, CPI(M), TMC, और अन्य पार्टियों और विपक्षी नेताओं ने CJP को अपना खुला समर्थन दिखाया है।

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद सहित कई नेताओं ने आंदोलन के प्रति एकजुटता दिखाई। यदि विपक्षी दल इस मुद्दे को केवल चुनावी भाषणों तक सीमित रखते हैं और जमीन पर चल रहे आंदोलनों से दूरी बनाए रखते हैं, तो युवाओं का भरोसा कमजोर होगा।विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी बात की है कि क्या विपक्ष युवाओं के सबसे बड़े आंदोलन पर एकजुट होकर खड़ी हो पाएगी, या फिर हर दल अपनी-अपनी राजनीतिक सीमाओं में ही बंधा रहेगा?

सड़क हादसे में प्रयागराज के श्रमिक की महाराष्ट्र के (नासिक) में ट्रक हादसे में हुई दर्दनाक मौत

(जीएनएस)। प्रयागराज। सरायममरेज -थाना क्षेत्र के ग्राम मोहउद्दीनपुर मियां का पूरा निवासी का एक मजदूर का महाराष्ट्र नासिक में सड़क हादसे से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान मुन्ना लाल प्रजापति (48 वर्ष)पुत्र छोटेलाल प्रजापति है। वह नासिक में लिमिटेड कंपनी के एक कार्यरत मजदूर थे। परिजनों के अनुसार बताया गया की 10 जुलाई की रात 11:00 बजे मुन्नालाल कंपनी के श्रमिकों को फ्लाईओवर (ब्रिज)पर छोड़ने गया था श्रमिक वहां से उतरकर दूसरी तरफ रोड पार करने के लिए जा रहा था तभी अचानक तेज रफ्तार में आ रही ट्रेलर की चपेट में आ गया और हादसा इतना भीषण था कि मुन्ना लाल प्रजापति की मौके पर मौत हो गई। जो कि शरीर की काफी अंग भी कुचल गया था। आरोप यह है कि ट्रेलर चालक ने पूरी तरह नशे की हालत में वाहन चला रहा था। और

घटना के सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। परिजनों का कहना है कि जिस कंपनी में मुन्नालाल कार्यरत थे उस कंपनी के मालिक ने पूरी तरह सहयोग की और मृतक मुन्ना लाल प्रजापति के शव को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था किया। मृतक अपने पीछे अपनी पत्नी सुनीता देवी और दो पुत्र अर्पित और अंशु एवं एक पुत्री अंकिता को इन छोटे- छोटे बच्चों को छोड़कर चले गये। सोमवार को जब दोपहर 1:00 बजे के लगभग जैसे ही शव गांव में पहुंचा परिजनों का रो - रो कर बुरा हाल हो गया। पत्नी एवं बच्चों और घर वालों का रोना, बिलखना, तड़पना देखकर हजारों की संख्या में लगी भीड़ में सभी लोगों की आंखे आंसुओं से भर गई और सभी ग्रामीणों ने शव की अंतिम विदाई करने के लिए उनके घर पर पहुंचे।

राजकीय महाविद्यालय हेमपुर के वार्षिकोत्सव में पहुंचे विधायक विवेक वर्मा, मेधावी छात्र-छात्राएं सम्मानित

(जीएनएस)। पीलीभीत/बीसलपुर/हेमपुर। क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय हेमपुर में वार्षिक पारितोषिक वितरण एवं प्रतिभा अलंकरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में 130 विधानसभा क्षेत्र बीसलपुर के लोकप्रिय विधायक विवेक वर्मा ने शिरकत की। समारोह के दौरान उन्होंने शैक्षणिक, सांस्कृतिक और खेलकूद गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार एवं स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।

कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि विधायक विवेक वर्मा द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की गई। इसके बाद महाविद्यालय प्रशासन और छात्र-छात्राओं द्वारा मुख्य अतिथि का भव्य स्वागत व अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने रंगारंग

शिक्षा के साथ-साथ इस तरह के रचनात्मक मंच विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद जरूरी हैं। क्षेत्र के युवाओं को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं दिलाना हमारी प्राथमिकता है।"

सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

विधायक विवेक वर्मा का संबोधन:

"युवा ही देश का भविष्य और राष्ट्र निर्माण की असली ताकत हैं।

— विवेक वर्मा, विधायक (बीसलपुर)

विधायक ने सभी पुरस्कार विजेता छात्र-छात्राओं को बधाई दी और अन्य विद्यार्थियों को भी जीवन में कड़ी मेहनत कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने महाविद्यालय के विकास के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया।

समारोह के दौरान साल भर विभिन्न प्रतियोगिताओं में अव्वल रहे मेधावियों को जब विधायक के हाथों मंच पर पुरस्कार मिले, तो उनके चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय के प्राचार्य ने मुख्य अतिथि विधायक विवेक वर्मा सहित सभी आगंतुकों और क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान कॉलेज का समस्त स्टाफ, सैकड़ों छात्र-छात्राएं और क्षेत्र के प्रबुद्ध जन मौजूद रहे।

'देश में सब बिकाऊ', भूख हड़ताल के 16वें दिन छलका सोनम वांगचुक' का दर्द, पीएम मोदी से बोले- संवेदनशीलता दिखाइए

(जीएनएस)। नीट-यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर शुरू हुआ उखळ का आंदोलन अब एक राजनीतिक बहस का रूप लेता जा रहा है। जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार के समर्थक सोनम वांगचुक पिछले 16 दिनों से जंतर-मंतर पर अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

उनकी लगातार गिरती सेहत को लेकर पूरा देश चिंतित है। अभिजीत दीपके की ओर से जारी ताजा हेल्थ अपडेट के मुताबिक, अब तक वांगचुक का 8.5" वजन कम हो चुका है और ब्लड प्रेशर भी काफी ऊपर नीचे हो रहा है।

भूख हड़ताल के 16 दिन...लेकिन सरकार अब भी खामोश

सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि संसद भवन से महज कुछ ही दूर जंतर मंतर पर देश का एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है लेकिन सरकार की ओर अब तक कोई पहल सामने नहीं आई है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि केंद्र सरकार लगातार अपनी बेरुखी दिखाते हुए चुप्पी साधे क्यों बैठी है।

अगर देश भर में नीट समेत कई पेपर लीक और इसके कारण कई बच्चों की जिंदगी खत्म करने की जवाबदेही शिक्षा मंत्री की नहीं है तो इसका जवाब किससे मांगा जाए? वांगचुक की मांग केवल एक मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका मानना है कि देश की परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुधार जरूरी हैं।

"धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अंत नहीं, जवाबदेही की शुरूआत है"

इंडियन एक्सप्रेस हिंदी को दिए इंटरव्यू में वांगचुक कहते हैं कि उनकी लड़ाई केवल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं है। अगर आज परीक्षा प्रणाली में हो रही गड़बड़ियों को नजरअंदाज किया गया, तो इसका असर आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ेगा। वो कहते हैं कि, "देश में सब कुछ बिकाऊ होता जा रहा है और ईमानदारी की कीमत लगातार कम होती जा रही है।"

जब उनसे पूछा गया कि क्या इस्तीफे से सब कुछ ठीक हो जाएगा...इसके जवाब में वांगचुक कहते हैं, सोनम वांगचुक का मानना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ अभियान नहीं है, बल्कि जवाबदेही तय करने की दिशा में पहला कदम है। यदि सरकार जिम्मेदारी तय नहीं करेगी तो मनमाने फैसले और लापरवाही का सिलसिला जारी रहेगा। यह केवल शिक्षा की समस्या नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है।

वांगचुक ने सरकार से पूछा सवाल- बच्चों का भविष्य कहां जा रहा

सोनम वांगचुक ने एक जिम्मेदारी के तौर पर सवाल उठाया कि यदि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का पेपर लीक होगा और नकल के जरिए डॉक्टर बनेंगे, तो भविष्य में मरीजों का इलाज कौन करेगा? अगर इंजीनियर भी इसी तरह परीक्षा पास करेंगे, तो उनके बनाए पुल और इमारतें कितनी सुरक्षित होंगी? उन्होंने सरकार को कटघरे में रखते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की कीमत केवल छात्रों तक नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है।

सरकार को जिद्दी नहीं संवेदनशील होना चाहिए

अनशन का ये 16वां दिन है बावजूद सरकार की इस बेरुखी पर सोनम वांगचुक हैं कि केंद्र सरकार की ओर से अब तक उनसे किसी प्रकार का संपर्क नहीं किया गया है। हालांकि, अब उनकी कोशिश है कि आंदोलन की आवाज और अधिक लोगों तक पहुंचे, ताकि सरकार इस मुद्दे की गंभीरता को समझ सके। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार संवेदनशीलता दिखाएगी और जल्द समाधान की दिशा में कदम उठाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अपने संदेश में सोनम वांगचुक ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता की आवाज होती है। पीएम को लोगों की भावनाएं समझनी चाहिए और जिद के बजाय संवेदनशीलता दिखानी चाहिए।

हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को लेकर राजनीतिक रंग दिए जाने की भी खूब चर्चा हुई।

आमिर खान के खिलाफ कही गई ऐसी बात

(जीएनएस)। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान अपनी तीसरी शादी के बाद से लोगों के निशाने पर आ गए हैं। 2 हिंदू महिलाएं और एक ईसाई महिला से शादी करने के बाद से आमिर खान विवादों में घिर गए हैं। आपको बता दें कि आमिर खान की दोनों एक्स वाइफ (रीना दत्ता और किरण राव) हिंदू थीं जबकि एक्टर की तीसरी पत्नी गौरी स्प्रैट ईसाई धर्म को मानती हैं।

आमिर खान के खिलाफ फतवा जारी

गौरी स्प्रैट के साथ आमिर खान की शादी ने देशभर में हलचल मचा दी है। कुछ लोगों को ये बात रास नहीं आ रही है। करणी सेना, बजरंग दल से

लेकर कई धर्मगुरु, आमिर खान की तीसरी शादी का जमकर विरोध कर रहे हैं। फिलहाल मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता के शाही चीफ मुफ्ती मौलाना ईफराहिम हुसैन (क़ा ल्थ़र३ल्ल) ने आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर फतवा जारी कर दिया है।

मुफ्ती मौलाना ईफराहिम हुसैन ने आमिर खान को लेकर एक वीडियो बनाया है जो कि इस समय इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह अपनी बात लोगों के सामने खुलकर रख रहे हैं। उन्होंने वीडियो में कहा है- आमिर खान ने तीसरी शादी एक गैर-मुस्लिम खातून के साथ की है। हमने देखा कि समाज में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अल्लाह का जो पैगाम है वो समाज के सामने पेश किया जाए।

मुफ्ती मौलाना ने कहा- ऐसा मुस्लिम मर्द गुनहगार है

मुफ्ती मौलाना ईफराहिम हुसैन ने कहा- अल्लाह का कुरान में हुकूम है कि मुस्लिम मर्द के लिए ईमान वालों के लिए ईमान वाली मुस्लिम औरतों से शादी करना जायज है।